



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनानद गोरखपुर में
विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व
शिलान्यास करते, उद्यमियों को भूखंडों का
आवंटन पत्र वितरण करते हुए।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एकरान इंडिया



वर्ष: 12 अंक: 250 पृष्ठ: 12

RNI : HPHIN/2012/48072



actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड

फार्स्ट न्यूज

देश में केरल समेत नौ राज्यों में निपाह वायरस का खतरा

टीम एक्शन इंडिया/नई दिल्ली
केरल में पिछले 24 घंटों में निपाह से संक्रमित कोई मामला सामने नहीं आया है। इससे संक्रमित नौ साल के बच्चा वैकल्पिक से बहर आ गया है। केरल की राज्यत्व संघीय पीना जैन के मुख्यालय बच्चे की सहत में अब सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस निपाह वायरस का खतरा केरल समेत देश के नौ राज्यों में है। इस पर आईसीएमआर और डब्ल्यूचॉर्प द्वारा किए अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह निपाह संक्रमण द्वारा दर्दों से होता है।

उन्होंने बताया कि केरल में हमें जो वायरस मिला है, उसका पहचान भारतीय जीनोटाइप या आई जीनोटाइप के रूप में की गई है, जो बालादेश में पाए जाने वाले स्ट्रेन के जैसे है। निपाह वायरस के एक मरोनियाई और दूसरा बालादेश से आया है। उन्होंने बताया कि राज्य में निपाह को लेकर रिश्ति संतोषजनक है। निपाह संक्रमित मरीज के सार्वजनिक में आने वाले लोगों की सूची बतार की गई है। 1233 लोग अब संपर्क सूची में हैं। 23 लोगों को मैटिकल कॉलेज में भर्ती करता रखा गया है। अस्पताल में 4 लोग हैं। उन्होंने बताया कि निपाह से निपटने के लिए अब तक 36 चमगांड़ों के नमूने एकत्र किए गए और परीक्षण के लिए भेजे गए। इसके साथ 34,167 घरों में हाउस विजिट पूरा हो चुका है। उच्च जोखिम वाली सार्क और सूची में 352 लोग हैं। जिन स्थानों पर निपाह वायरस की पुष्टि हुई है, वहाँ रखार्य कर्मियों ने रक्षाम गतिविधि तेज कर दी है।

टीम एक्शन इंडिया/नई दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र का आगाज 18 सितंबर को आयोजित किया गया है। निपाह संसद के साथ 75 सालों के संसद के सफर पर भी चर्चा की गई। पुराने संसद भवन के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने तमाम वादों को ताजा किया। बता दें कि संसद की आगे कार्यवाही 19 सितंबर (मंगलवार) से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी।

पीएम मोदी ने की पुराने संसद भवन में आखिरी स्पीच पुराने संसद भवन को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52 मिनट की आखिरी स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने देश के पूर्व

सत्र है 'विशेष', पीएम मोदी का 'संदेश'

= पुराने संसद भवन के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने तमाम वादों को ताजा किया, संसद की आगे कार्यवाही 19 सितंबर (मंगलवार) से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी।

वादों में पुराना संसद

8 पीएम मोदी के संबोधन के साथ 75 सालों के संसद के सफर पर भी चर्चा की गई।



गंगत सिंह और बुद्धकेश्वर की बहादुरी को किया गात

अपने 52 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भगत सिंह और बुद्धकेश्वर दत की बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा कि विंसिंह साम्राज्य की नीद से जगाने के लिए भगत सिंह और बुद्धकेश्वर दत ने संसद की आगे कार्यवाही 19 सितंबर (मंगलवार) से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी।

प्रधानमंत्रियों को याद किया। पीएम मोदी ने की पुराने संसद भवन में आखिरी स्पीच पुराने संसद भवन को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 52 मिनट की आखिरी स्पीच दी।

गंगत सिंह भी उन लोगों की रातों की नीद हरगम कर देती है, जो इस देश का भला नहीं बाते हैं। मोदी ने कहा कि इसी संसद में पंडित नेहरू ने आधी रात को अपना "नियति से साक्षात्कार" भगवन दिया था और उनके शब्द आज भी सभी को प्रेरित करते हैं।

पुरानी संसद की "उपलब्धियां, अनुभव, चार्चे और सीख" पर बाल पीएम: इसके साथ ही लोकसभा में "संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा" पर चर्चा करते हुए पीएम ने लोकसभा को मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 'वोट के बदले

नकद' घोटाला भी याद दिलाया। साथ ही उन्होंने पुरानी संसद में "उपलब्धियां, अनुभव, चार्चे और सीख" विषय पर चर्चा करते हुए कहा जाते रहते हैं।

वाजपेयी सरकार के पलों को किया याद: पीएम मोदी ने वाजपेयी सरकार के पलों को याद करते हुए कहा कि जब वाजपेयी के समय में उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के तीन नए राज्य बनाए गए थे तो हर जाह जरूर का मौहाल था, लेकिन साथ ही इस बात पर उन्होंने अफसोस की जाताया कि आधु प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाए जाने से दोनों राज्यों में केवल कड़वाहट और खनन-खराबा हुआ।

इस शिखर सम्मेलन के परिणाम परिवर्तनकारी हैं और आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया आकर देने में योगदान देंगे। धनखड़ ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली के राजघाट पर विश्व नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। यह एक अद्भुत दृश्य था।



केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र का आगाज 18 सितंबर को होने से पूर्व पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब होते हुए।

जी-20 के सफल आयोजन से भारत का दुनिया में बढ़ा कद: धनखड़

'5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद हो सीट शेयरिंग'

टीम एक्शन इंडिया/हेदराबाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद की जाए। हेदराबाद में 16-17 सितंबर को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी हाईकमान से इसकी मांग की है। यह मांग करने वाले ज्यादातर नेता उन राज्यों से हैं, जहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी से है। इन नेताओं को भरोसा है कि पार्टी 5 राज्यों को विधानसभा चुनावों में अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे वे सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में रहेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तीरोंको की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि अगले महीने के पहले हप्ते में इसका ऐलान हो जाए।

खाते में सीधी पेंशन अब नहीं कोई टेंशन

जो ठगा वो कर दिखाया – सामाजिक सुरक्षा में आगे हादियाणा



- देश में सर्वाधिक ₹2750 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दराए में बढ़ोत्तरी महागाई के अनुसार
- बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा, अब तक 1 लाख 7 हजार 4 दुर्घजानों व 13 हजार दिव्यांगों की पेंशन घर बैठे शुरू
- बुढ़ापा पेंशन के लिए आय की पात्रता सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख वार्षिक की

"नागरिकों के संरक्षिकरण और सम्मान के लिए बीते वर्षों में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए हैं। चाहे वो स्वरोज़गार हो या फिर सामाजिक सुरक्षा, आज अनेक योजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं।"

नरेन्द्र मोदी



ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल के तेनजिंग रब्बा ने जीता चांदी

टीम एक्शन
इंडिया/हामीरपुर/विवेकानन्द वाशिष्ठ

हिमाचल प्रदेश स्टेट राफ़क लैप्सीसिप्सन द्वारा इंदिरा गांधी एचपी स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, शिमला में आयोजित 7वीं एचपी स्टेट इंटर स्कूल चैपियनशिप प्रतियोगिता में ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों ने भाग लिया था।

इंडिया गांधी खेल परिसर शिमला में शूटिंग चैपियनशिप में प्रेदेश से 115 खिलाड़ियों ने साधा निशाना जिसमें उदय, तेनजिंग रब्बा और सोनम ने जीत अपने नाम की और नेशनल इंटर स्कूल के लिए चयनित हुए। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के निदेशक राजीव

कुमार ने विजेताओं को सम्मानित किया। मीके पर स्कूल प्रबंधक कुलबीर सिंह और प्रिंसिपल डायरेक्टर पूजा मिहास भी उपस्थित रही। अगली प्रतियोगिता अक्टूबर महीने में कुफी सी में होगी।

अम्बाला शहर में बनेगा इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

= रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंग व शोरुम बना चुके लोगों के लिए जल्द पॉलिसी लेकर आएगी सरकार-मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री ने अंबाला में किया जनसंवाद

कार्रवाई के आदेश

8 जहां अभी भी रेजिडेंशियल इलाकों को कमर्शियल किया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएँ:



हमने पुराने सिटीम को बदलकर लीकेज योकी: सीएम मनोहर

मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्यों के मामले में हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम करवाए हैं और कम पैसों में करवाए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वे गांवों के लिए 1 रुपया भजते हैं लेकिन धरातल पर बस 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने सरकार बनाकर सिस्टम की इस लीकेज को रोका है। हमने

व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले छोटे-छोटे काम के लिए दफ्तरों के चक्रवर्काल नाकरण पड़ते थे लेकिन अब घर बैठे काम हो रहे हैं। राज्य सरकार ने आशुमान और चिरायु हरियाणा के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के मुपर इलाज की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे सरकारी नौकरियां मिलती थीं, सभी को पता है लेकिन हमने बिना पर्यां और

बिना खर्चों के नौकरी देने का काम किया है। जनसंवाद में तकाल बनाई गई 5 लोगों की पेशन: जनसंवाद के दोरान मुख्यमंत्री ने 5 लोगों की तकाल पेशन बताई है। इनमें अधिनियम कुमार, विजय कुमार, रविंद्र कुमार, निजमीन और रोशनी देवी शमिल हैं। इसके अतिरिक्त वांड-12 और 15 में कन्फ्यूनीट सेंटर की मांग पर मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों को फिजिलिटी थैंक रने के निर्देश दिए। इसके साथ-साथ एक महिला ने इंतकाल का विषय उत्ताप्ता तो मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त डॉ. शालीन को सोमवार सुहृद उसका इंतकाल प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। इस मोक्ष पर उपायुक्त डॉ. शालीन, पॉलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंगवा, सहृत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

आबादी के हिसाब से तय की शहरों की ग्रांट: सीएम मनोहर

जनसंवाद के दोरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों व ग्रामीण क्षेत्र में अपने मन मुताबिक विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाती थी, लेकिन अब हमने तय किया है कि आबादी के हिसाब से ग्रांट दी जाएगी। किसी भी शहर की 31 दिसंबर को जो आबादी होगी, उसके हिसाब से अगले वर्ष प्रति वर्ष 2500 रुपये की ग्रांट शहर को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी फैसला आईडी की वजह से संभव हो पाया है। हर शहर में किन्तु आबादी है, फैसला आईडी में सभी का रिकॉर्ड है। इसी वजह से आज घर बैठे लोगों की पेशन बन रही है और अनेक काम हो रहे हैं।

इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईडीसीसी) बनाया जाएगा। इसका पैसा सरकार देगा।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, करसाल की ओर तज एवं वहां भी इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, ताकि ट्रैफिक व अपाराधिकों पर और जैन नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए कि शहर का सर्वे करवाया जाए, जहां जहां सीरीजीटी नहीं हैं, वहां सीरीजीटी लोगों की व्यवस्था की जाए। शहर की मार्किट में डुकनदार, अनाज मंडी में आदीनी और बाजार में नार नियम कैमरे लगाएं। इन कैमरों को युलिस इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मुख्यमंत्री ने अंबाला शहर में बनाया इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कंट्रोल करेंगे।

पुलिस महानिदेशक ने ली उच्च अधिकारियों की बैठक

= हेल्पलाइन नंबर -112 पर महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट के माध्यम से भी किया जाएगा लिंक जनरेट



दो प्रशिक्षित व्यक्ति लगाए जाएंगे जो पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। बैठक में शत्रुजीत कपर द्वारा पुलिस जांच की गई। कपर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पुलिस थानों में जांच की प्रशिक्षण युग्मतापूर्ण हो ताकि स्टीक तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कार्य में युग्मतासुनिश्चित करने तथा क्षमता नियमांने के लिए एक लोगल एडवाइजर

की नियुक्ति की जाएगी। लीगल एडवाइजर द्वारा जांच के दोरान समय समय पर कानूनी मार्गदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुलिस थानों में जांच की प्रशिक्षण युग्मतापूर्ण हो ताकि महिलाओं का विकास तथा कार्यकारी व्यवस्था का उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए एक्टिविटी कैलेंडर तैयार करवाएं और उसके अनुरूप इकानी प्रशिक्षण दें। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कार्य में युग्मतासुनिश्चित करने तथा क्षमता नियमांने के लिए हारियाणा पुलिस वचनबद्ध है। प्रदेश में

महिलाएं ना केवल घरों में बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसे लेकर विभाग द्वारा कई महसूस प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द 112 की वेबसाइट पर महिलाओं का डेटाबेस तैयार करने को लेकर तिक्क जनरेट किया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षण संस्थानों, कार्पोरेट सहित अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के सहयोग से इस वेबसाइट पर महिलाओं का डाटा अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक जब कभी महिला हैल्पलाइन नंबर 112 पर फोन अथवा व्हाट्सएप करेगी तो उससे संबंधित जानकारी तैयार कर्मचारी के पास अपने आप पहुंच जाएगी।

महिलाएं ना केवल घरों में बल्कि

आशा वर्कर्स का केंद्रीय राज्यमंत्री के कार्यालय पर प्रदर्शन

मंथन

8 कभी महिला हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन अथवा व्हाट्सएप करेगी तो उससे संबंधित जानकारी तैयार कर्मचारी के पास अपने आप पहुंच जाएगी।

महिलाएं ना केवल घरों में बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसे लेकर विभाग द्वारा कई महसूस प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द 112 की वेबसाइट पर महिलाओं का डेटाबेस तैयार करने को लेकर तिक्क जनरेट किया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षण संस्थानों, कार्पोरेट सहित अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के सहयोग से इस वेबसाइट पर महिलाओं का डाटा अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक जब कभी महिला हैल्पलाइन नंबर 112 पर फोन अथवा व्हाट्सएप करेगी तो उससे संबंधित जानकारी तैयार कर्मचारी के पास अपने आप पहुंच जाएगी।



लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वर्कर्स के लिए जारी रखी गई व्यवस्था के अधिकारी के लिए वर्कर्स ने तो जीवंत वर्कर को उनके आक्रमक तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई। सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन और सरकार के विभाग के प्रति धोर उपेक्षापूर्ण रूप से कंट्रोल वर्कर के बिल्कुल आशा वर्कर को उनके कार्यक्रम के तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन और सरकार के विभाग के प्रति धोर उपेक्षापूर्ण रूप से कंट्रोल वर्कर के बिल्कुल आशा वर्कर को उनके कार्यक्रम के तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के अफिस के सामने जारी रखी गई व्यवस्था के अधिकारी के लिए वर्कर को उनके आक्रमक तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

जिसके बाद भी बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के अफिस के सामने जारी रखी गई व्यवस्था के अधिकारी के लिए वर्कर को उनके आक्रमक तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

जिसके बाद भी बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के अफिस के सामने जारी रखी गई व्यवस्था के अधिकारी के लिए वर्कर को उनके आक्रमक तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

जिसके बाद भी बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के अफिस के सामने जारी रखी गई व्यवस्था के अधिकारी के लिए वर्कर को उनके आक्रमक तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

जिसके बाद भी बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के अफिस के सामने जारी रखी गई व्यवस्था के अधिकारी के लिए वर्कर को उनके आक्रमक तंत्र के देखते हुए बैरीकेंडिंग हटाने पड़ गई।

जिसके बाद भी बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स ने केन्द्रीय राज्यमंत्री गुर्जर के अफिस के सामने ज

नियमित योग व पौष्टिक आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी: डीसी विक्रम सिंह

टीम एक्शन इंडिया/फरीदाबाद (हरपाल सिंह यादव) डीसी विक्रम सिंह के निदेशनुसार जिला फरीदाबाद में पोषण माह का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यकारी सुरेखा देवी की अध्यक्षता में एनआईटी-2 में अंगनवाड़ी कार्यकारी और लिए योग प्रशिक्षण कैम्प आयोजन किया गया। अनुषुष विभाग से योग शिक्षक विकास यादव द्वारा सभी कार्यकारी और योग के महत्व के बारे में बताया गया और योग सिखाया गया। परियोजना अधिकारी सुरेखा देवी द्वारा 0-6 महीने के बच्चों के लिए माँ के दृढ़ के महत्व के बारे में बताया गया। महिला एवं बाल



विकास परियोजना अधिकारी सुरेखा देवी ने कहा कि पोषण

माह के तहत विभाग द्वारा अध्ययन चलाया जा रहा है,

जिसमें कुपोषण से पीड़ित बच्चों और महिलाओं को जागृति मिलेगी और वे अपनी खुकाकी की ओर पूरा ध्यान देंगे। ताकि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि यदि कोई बच्चा पोषण लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा तो नियम स्वरूप से वे इसकी जानकारी अपने परिवार में साझा करेंगे, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रतिबद्ध होगा तो नियम स्वरूप से अपने परिवार में साझा करना चाहिए। हर महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहती है।

इसके लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती महिला को ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जो उसके गर्भस्थ शिशु का पोषण करें। उन्होंने महिला एवं बाल विकास यादव द्वारा अवेदन के माध्यम से जाने वाली विभान जन कल्याण योजना एवं और निर्देश जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंचना योजना, समृद्ध पोषणार, अति के बारे में जानकारी दी। पोषण जागरूकता अधियान में कार्यकारी योग्य और स्थायी नियमों से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही जिला बाल संस्करण इकाई से प्रवेषण कुमार ने भी

टीम एक्शन इंडिया/फरीदाबाद (हरपाल सिंह यादव)

एवं बाल विकास विभान के निदेशक के आदेशनुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेस महिला विभान के कुशल मार्गदर्शन में आज आज मुजेसर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय प्राइमरी विद्यालय में "लिटरेसी अवेदनरेस कार्यक्रम" के अंतर्गत कैम्प में जानकारी अवेदन किया गया। जिसमें बच्चों को जेजे एवं, पास्को एक सहित अन्य कानूनी जानकारी दी। कैम्प में एडवॉकेट जीत सिंह रावत, पीएलवी हरदीप कौर, पीएलवी करण द्वारा बच्चों को पोषण अधियान की शिक्षण दिलाकर कार्यक्रम कार्यक्रम का समापन हुआ।



पास्को एक्ट, जेजे एक्ट पर प्रकाश डाला। जिला बाल कल्याण अधिकारी एसएल खन्ना ने भी बच्चों के सम्मुख अपने विचार रखें और बच्चों से अनुरोध किया कि वह अपने फोटोबैक लिखकर उपलब्ध करायें। जिससे बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करते हुए बताया कि, की किसी अनजान व्यक्ति के किसी भी

डीसी विक्रम सिंह की राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के केसों की समीक्षा

समीक्षा बैठक



8 डीसी ने कहा, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान गम्भीरता से करें अधिकारी

टीम एक्शन इंडिया/फरीदाबाद (हरपाल सिंह यादव) डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आज सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला फरीदाबाद में लिखित राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के केसों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान अधिकारी गम्भीरता से करें। डीसी विक्रम सिंह ने एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जस्ती दिशा-निर्देश दिए। डीसी विक्रम सिंह ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान अधिकारी गम्भीरता से करें। बता दें विगत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रदेश अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधत अधिनियम 1982, जैव विविधत अधिनियम 2002 एवं नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत पर्यावरण बचाव और संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और शांतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुत्तम और शत्रुपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली तथा तीव्र गति से निपटान करने के लिए किया गया।

प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के तहत सुनवाई कर सकता है। बनाये वायर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रदेश अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधत अधिनियम 1982, जैव विविधत अधिनियम 2002 एवं नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत पर्यावरण बचाव और संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और शांतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुत्तम और शत्रुपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली तथा तीव्र गति से निपटान करने के लिए किया गया।

यह एक विशिष्ट नियाय है, जो कि पर्यावरण विवादों वह—अनुशासनिक मामलों सहित, सुविज्ञानीय तंत्रों से संचालित करने के लिए सभी विवादों तंत्रों से सुरक्षित है। यह अधिकारी गम्भीरता से उपस्थित है।

वहीं उन्होंने बैठक में एनजीटी के टोटल 16 केसों के केसों की एक-एक कार्यकारी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक में उपस्थित है।

उन्होंने बैठक में उपस्थित है।

प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के तहत सुनवाई कर सकता है। जनता वायर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रदेश अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधत अधिनियम 1982, जैव विविधत अधिनियम 2002 एवं नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत पर्यावरण बचाव और संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और शांतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुत्तम और शत्रुपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली तथा तीव्र गति से निपटान करने के लिए किया गया।

यह एक विशिष्ट नियाय है, जो कि पर्यावरण विवादों वह—अनुशासनिक मामलों सहित, सुविज्ञानीय तंत्रों से संचालित करने के लिए सभी विवादों तंत्रों से सुरक्षित है। यह अधिकारी गम्भीरता से उपस्थित है।

वहीं उन्होंने बैठक में एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का समीक्षा बैठक आयोजित करना चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित है।

उन्होंने बैठक में उपस्थित है।

प्रतिबद्ध नहीं है। लेकिन प्रकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों के तहत सुनवाई कर सकता है। जनता वायर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रदेश अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, जल उपकरण अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधत अधिनियम 1982, जैव विविधत अधिनियम 2002 एवं नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत पर्यावरण बचाव और संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और शांतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुत्तम और शत्रुपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली तथा तीव्र गति से निपटान करने के लिए किया गया।

यह एक विशिष्ट नियाय है, जो कि पर्यावरण विवादों वह—अनुशासनिक मामलों सहित, सुविज्ञानीय तंत्रों से संचालित करने के लिए सभी विवादों तंत्रों से सुरक्षित है। यह अधिकारी गम्भीरता से उपस्थित है।

वहीं उन्होंने बैठक में एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि

